

प्रेषक,

आर.मीनाजी सुन्दरम्,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डेरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2018

विषय— वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत संचालित दुग्धशाला का सुदृढीकरण योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सम्पर्क कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-1596-98/नियोजन-दुग्धशाला का सुदृढीकरण पत्रा०-II/2017-18, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत संचालित दुग्धशाला का सुदृढीकरण योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत में रिटेनिंग वाल, हार्ड पार्क, सी०सी० अप्रोज रोड एवं बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य हेतु रू० 45.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू० 16.40 लाख (रुपये सोलह लाख चालीस हजार मात्र) आपके निर्वहन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत में रिटेनिंग वाल, हार्ड पार्क, सी०सी० अप्रोज रोड एवं बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य हेतु आगमन में आंकलित धनराशि रू० 60.20 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू० 45.01 लाख है।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगमन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आगमन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
 9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
 10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 11. शासनादेश संख्या-571/xxvii(1)/2010, दिनांक 18.10.2010 के दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाये।
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेंसी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि० को उपलब्ध करायी जाय।
 13. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 14. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
- 2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजना-10-दुग्धशाला का सुदृढीकरण-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-226/XXVII-4/2016, दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आरमीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 162 /XV-2/2015तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महासूचनाकार, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलाध्यक्ष, कुमार्क/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, दुग्ध को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।